



महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका : चन्दौली जनपद के धानापुर ब्लाक के वि"ीश सन्दर्भ में

अभय सिंह

शोध छात्र, महात्मा गांधी का"ी विद्यापीठ, वाराणसी

डॉ० पारस नाथ मौय

एसोसिएट प्रोफेसर महात्मा गांधी का"ी विद्यापीठ, वाराणसी

सारा"ी

स्वतंत्रता के पश्चात् से महिलाओं को आर्थिक क्रियाकलापों में स्वावलम्बी बनाना एवं उनकी उद्यमिता प्रवृत्ति का विकास करना अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में अन्तरनिहित विकास योजना प्रतिरूप का अभिन्न अंग रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनकी उत्पादन क्षमता के विस्तार, उनमें विपणन की कठिनाईयों की समझ, बचत एवं निवे"ी जैसी आर्थिक क्रियाओं की व्यावहारिक उपादेयता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार कई सारी योजनाएं चलाकर महिलाओं को स"िवक्त कर रही है। जिसमें स्वयं सहायता समूह का निमाण महत्वपूर्ण है। महिलाओं के स"िवक्तकरण एवं सामाजिक आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह ने वि"ीष योगदान दिया है। हाँलांकि चन्दौली जनपद के धानापुर ब्लाक के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में इसके विस्तार के साथ कुछ समस्याएं भी आयी हैं। जिसमें से दो समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। पहला विकास खण्ड में आर्थिक विषमता का होना एवं दूसरा विकास खण्ड में स्वरोजगार की कमी प्रमुख हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में धानापुर विकासखण्ड में चल रही स्वयं सहायता समूहों म सदस्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक वि"ीषण किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द – स्वयं सहायता समूह, महिला स"िवक्तकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मि"ीन, परिक्रमण निधि, सामूहिक निवे"ी निधि।

प्रस्तावना

आज का भारतीय समाज सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों की जटिल प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक तरफ प"ीचमी "ीक्षा, बढ़ता औद्योगिकीकरण लोगों के जीवन"ीली में व्यापक बदलाव ला रहा है तो वहीं बदलती कानून व्यवस्था एवं राजनैतिक आदर्"ी महिलाओं की स्थिति को काफी हद तक महत्वपूर्ण बनाती हैं। किंतु आज के परिवे"ी में नारियों की सामाजिक स्थिति विरोधाभासी द"ीाओं से गुजरती हुई नजर आती है।

ग्रामीण भारत की आबादी में बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। महिलाओं की गरीबी आर्थिक अवसरों और स्वतंत्रता के अभाव से सीधे सीधे जुड़ी हैं। निर्णय लेने में उनकी भागीदारी कम होती है क्योंकि उन्हें आर्थिक संसाधन, "ीक्षा और सहयोग आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है।

किसी भी सभ्य समाज की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक तरीका यह भी है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, उनको क्या – क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं तथा उनकी शैक्षिक स्तर कैसी है? जिन्होंने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है उनकी मौलिक संसाधनों तक कितनी पहुँच है और राजनैतिक या सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाये तो महिलाओं की स्थिति, विकास का एक प्रकार का संकेतक है। ग्रामीण से लेकर शहरी और राष्ट्रीय से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की स्थिति सुधारने के तमाम प्रयास किये गये हैं।



स्वयं सहायता समूह का विकास—

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारें ग्रामीण गरीब एवं वंचितों तक सूक्ष्म वित्त की पहुंच को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। सूक्ष्म वित्त एक प्रकार की बैंकिंग सुविधा है जो कम आय वाले व्यक्ति या समूह को दी जाने वाली राशि है। गरीबों तक सूक्ष्म वित्त को पहुंचाने के पीछे का कारण यह था कि सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। 1950 के दशक में भारत में व्यापक स्तर पर सहकारी बैंक खोले गये। बाद में 1969 में 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इस आन्दोलन को गति प्रदान की गयी एवं देश भर में बैंकों की शाखाएं खोली गयीं। इसका प्रभाव यह हुआ कि बैंकों पर लोगों की औसत निर्भरता कम हुई।

इसके बाद सरकार ने 1980 में कई ऋणों पर सब्सिडी देने वाले कार्यक्रम चलाये। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हुए। कारण यह था कि ग्रामीण जनता को कम ऋण की आवश्यकता थी, जबकि वित्तीय संस्थाएं बिना किसी गुणात्मक पहलू पर विचार किये अत्यधिक ऋण दे रही थी। जिसके कारण ऋणों की उत्पादकता शून्य हो गयी थी। वित्तीय रूप से यह व्यवहारपूर्ण नहीं था। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, जिसके बाद वित्तीय समावेशन में कई गुणात्मक सुधार हुए।

1992 में नाबार्ड द्वारा बैंक लिंकेज कार्यक्रम चलाया गया, जिसके कारण देश के सभी स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा गया। कालान्तर में सन् 1999 को सरकार ने पूर्व में चली आ रही छः योजनाओं (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार हेतु युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण महिलाओं को विकसित उपकरणों की आपूर्ति एवं मिलियन कूप योजना) का पुनर्गठन करके सम्मिलित रूप स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार प्रत्येक ब्लॉक में से 10 गतिविधियों का चयन करती थी एवं उनको आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करती थी। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार की गहन समीक्षा के बाद यह पता चला कि योजना को लागू करने में अत्यधिक अन्तर क्षेत्रीय विषमता, अपर्याप्त कौशल क्षमता का निर्माण, अपर्याप्त निवेश, बैंकों के साथ कम सम्पर्क आदि के कारण पर्याप्त उत्पादकता नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से सन् 2011 में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को सरकार द्वारा इन कमियों को दूर किया साथ ही साथ ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर सर्वव्यापी बनाया।

स्वयं सहायता समूह देश के असंगठित समूह को संगठित कर उन्हें आवश्यक वित्तीय सेवा और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करती है। ये सभी स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पोषित होते हैं। स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से वंचितों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराकर उनकी बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। स्वयं सहायता समूह सामाजिक आर्थिक स्वावलम्बन का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने इच्छित लक्ष्य को पूरा करने का समान अवसर मिलता है एवं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी सदस्य समान रूप से सहभाग भी करते हैं। वित्तीय सुविधा प्रदान करने के साथ साथ स्वयं सहायता समूह महिला सर्वाधिकारों में भी सहयोग करता है और अन्य विकासात्मक कार्य जैसे— शिक्षा, स्वस्थ, परिवार नियोजन, भूमि और पानी तक पहुंच को भी सुलभ करता है।



अध्ययन का उद्देश्य—

यह अध्ययन धानापुर विकासखण्ड में संचालित स्वयं सहायता समूह में कार्य कर रही महिलाओं के प्रदर्शन पर आधारित है। जिसमें महिलाओं के मुख्यतः दो पहलुओं पर विचार किया गया है।

- सदस्य महिलाओं की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक स्थिति।
- सदस्यों का समूह में सम्मिलित होने का कारण।

शोध प्रविधि—

अध्ययन में प्राथमिक आंकड़ों के माध्यम से 60 उत्तरदाताओं का दैव निर्दिष्ट प्रविधि के द्वारा चयन किया गया। द्वितीयक आंकड़ों में विभिन्न शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया गया है। आंकड़ों के आधार पर वर्णात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

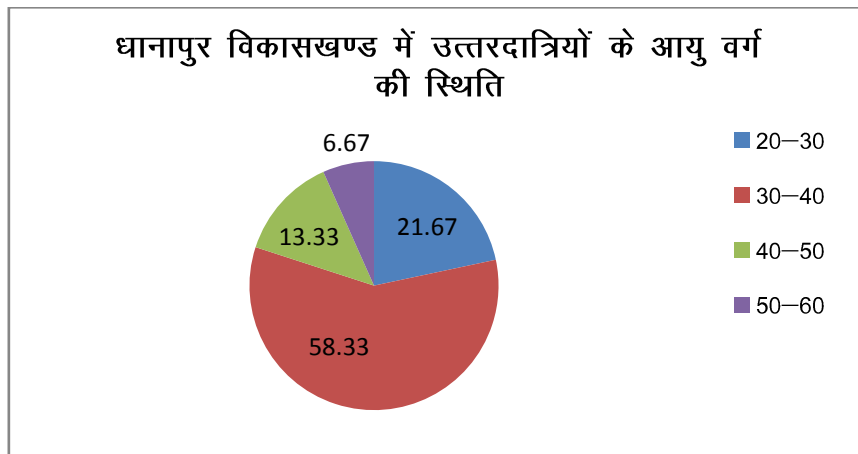
आंकड़ों का विश्लेषण

सारणी 1 से स्पष्ट है कि धानापुर विकासखण्ड में स्वयं सहायता समूह में कार्य कर रही महिलाओं के आयु वर्ग को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें 21.67 प्रतिशत महिला 20 से 30 वर्ष, 58 प्रतिशत महिला 30 से 40 वर्ष, 13 प्रतिशत महिला 40 से 50 वर्ष तथा 6.67 प्रतिशत महिला 50 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की हैं। अतः 30 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं विकासखण्ड में अधिक सक्रिय हैं।

सारणी-1

धानापुर विकासखण्ड में उत्तरदात्रियों के आयु वर्ग की स्थिति			
क्र०	आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	20-30	13	21.67
2	30-40	35	58.33
3	40-50	8	13.33
4	50-60	4	6.67
5	योग	60	100

Source: उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों से शोधकर्ता द्वारा स्वयं आंगणित।



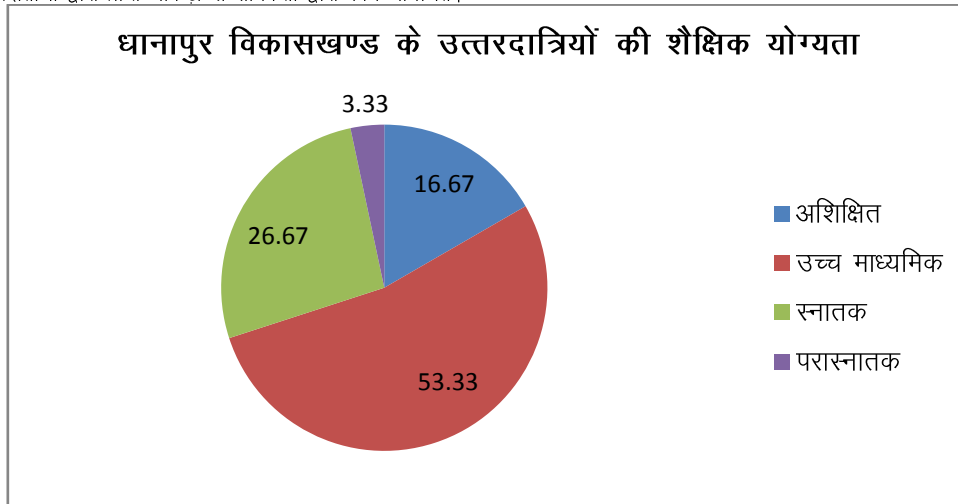


सारणी संख्या 2 के वि"लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 16.67 प्रति"त महिलाएं अ"शिक्षित, 53.33 प्रति"त महिलाएं उच्च माध्यमिक, 26.67 प्रति"त महिलाएं स्नातक तथा 3.33 प्रति"त महिलाएं परास्नातक तक की "िक्षा प्राप्त की हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि समूह में कार्य कर रही महिलाओं में अभी भी अ"शिक्षित महिलाएं अधिक है।

सारणी-2

धानापुर विकासखण्ड के उत्तरदात्रियों की शैक्षिक योग्यता		
शैक्षिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	10	16.67
उच्च माध्यमिक	32	53.33
स्नातक	16	26.67
परास्नातक	2	3.33
योग	60	100

Source: उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों से शोधकर्ता द्वारा स्वयं आंगणित।

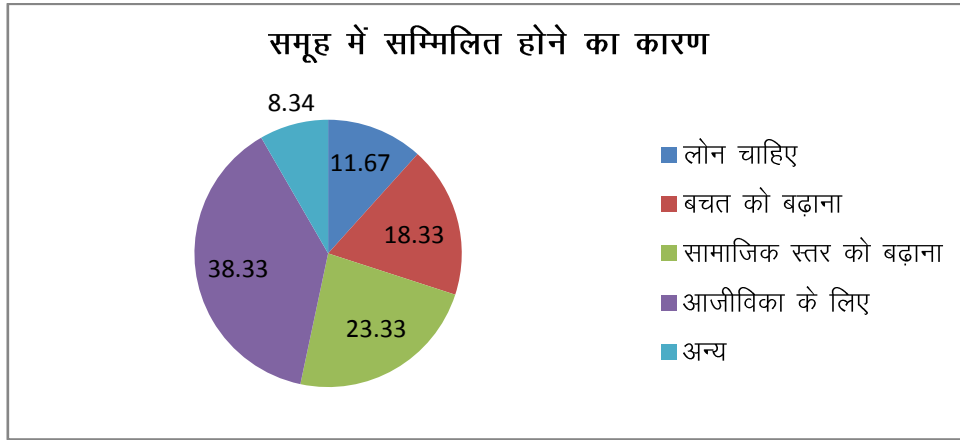


सारणी 3 में दिखाया गया है कि सदस्यों का समूह में शामिल होने का कारण क्या था। जिसमें 11.67 प्रति"त महिलाएं लोन के लिए, 18.33 प्रति"त महिलाएं बचत के लिए, 23.33 प्रति"त महिलाएं सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए, 38.33 प्रति"त महिलाएं आजीविका के लिए एवं 8.34 प्रति"त महिलाएं अन्य कारणों से समूह की सदस्य बनी हैं।

सारणी-3

समूह में सम्मिलित होने का कारण		
कारण	संख्या	प्रतिशत
लोन चाहिए	7	11.67
बचत को बढ़ाना	11	18.33
सामाजिक स्तर को बढ़ाना	14	23.33
आजीविका के लिए	23	38.33
अन्य	5	8.34
योग	60	100

Source: उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों से शोधकर्ता द्वारा स्वयं आंगणित।

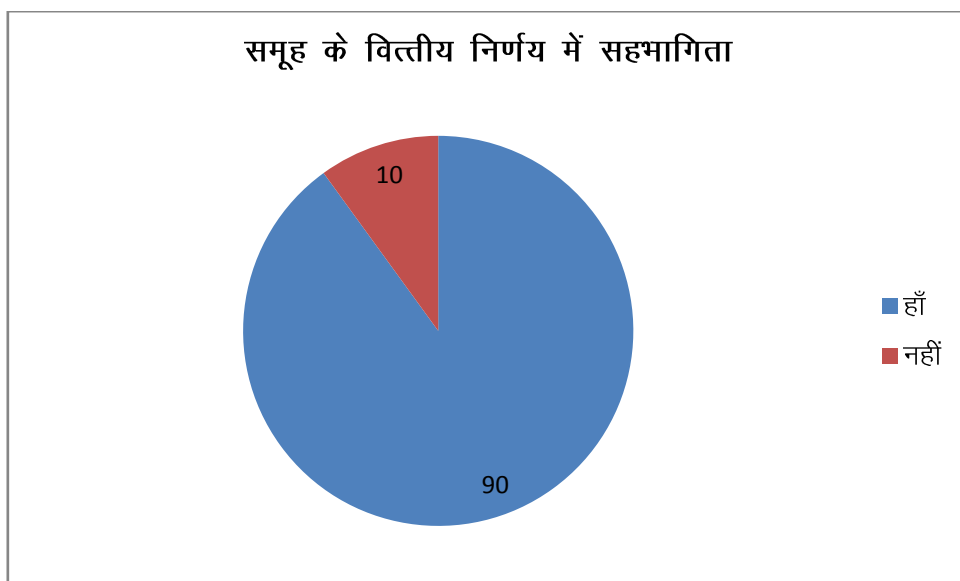


सारिणी 4 से स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता स्वयं सहायता समूह के वित्तीय निर्णय में रहती है जबकि 10 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता समूह के आर्थिक निर्णय में नहीं रहती है। अतः समूह से जुड़ी महिलाएं वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हुई हैं।

सारिणी-4

समूह के वित्तीय निर्णय में सहभागिता		
वित्तीय निर्णय में सहभागिता	संख्या	प्रतिशत
हाँ	54	90
नहीं	6	10
योग	60	100

Source: उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों से शोधकर्ता द्वारा स्वयं आंगणित।



सारिणी 5 से स्पष्ट है कि 70 प्रतिशत महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अपना नया व्यवसाय शुरू की हैं। 30 प्रतिशत महिलाएं अभी भी इतनी आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं हो पायी है कि

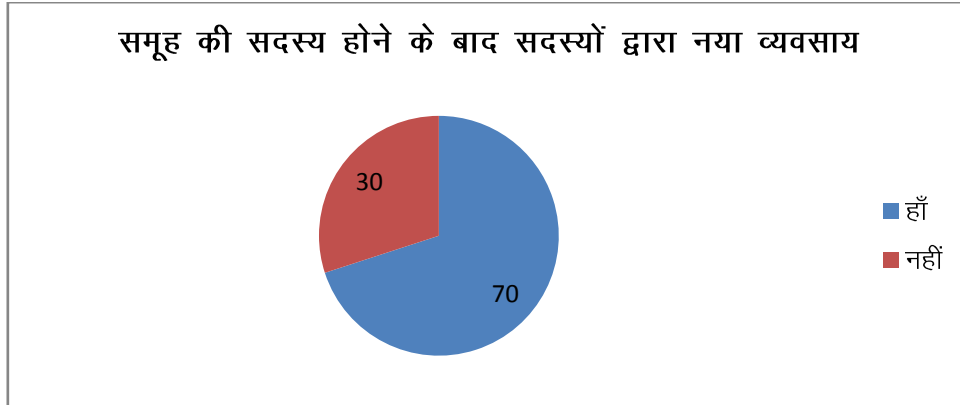


अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें। अतः समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने में सक्षम हुई हैं।

सारिणी-5

समूह की सदस्य होने के बाद सदस्यों द्वारा नया व्यवसाय		
नया व्यवसाय शुरू किया	संख्या	प्रतिशत
हाँ	42	70
नहीं	18	30
योग	60	100

Source: उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों से शोधकर्ता द्वारा स्वयं आंगणित।



निष्कर्ष—

आंकड़ों के वि"लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि धानापुर विकासखण्ड में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी आजीविका में वृद्धि, सामाजिक जीवन स्तर में सुधार तथा आर्थिक निर्णयों में सहभाग बढ़ा है। शिक्षा में अधिकतर महिलाएं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को स्वरोजगार करने में भी सहायता कर रहा है।



सन्दर्भ

1. Sinha, Navin (2021): “*Performance of Self help Groups in India,*” January 30, Vol LVI NO 5 EPW.
2. Kanitkar, Ajit (2002): “*Exploring Empowerment and Leadership at the Grassroots: Social Entrepreneurship in SHGs Movement in India,*” SAGE Publication pp 234-62.
3. Kropp, Erhard and B S Suran (2002): “*Linking Banks and Self Help Groups in India – An Assessment,*” paper presented at SHG- Bank Linkage Programme Seminar, NABARD, New Delhi, 25-26 November.
4. Ansari, S A (2013): “*SHG Bank Linkage Programme in India: An Overview,*” Scholars World, Vol 1, No 1, pp 12–19.
5. Agarwal, R (2016): “*Banks Race to Targets, Rural Women’s Groups to Defaults,*” IndiaSpend, 20 August, <https://archive.indiaspend.com/cover-story/banks-race-to-targets-rural-womens-groups-to-defaults-68113>
6. Ramesh, Jairam (2007): “*Self-help Groups Revolution: What Next?*” Economic & Political Weekly, Vol 42, No 36, pp 3621–24.
7. Dasgupta, R (2005): “*Microfinance in India: Empirical Evidence, Alternative Models and Policy Imperatives,*” Economic & Political Weekly, Vol 40, No 12, pp 1229–37
8. RBI (2020): *Handbook of Statistics on Indian Economy 2019–20*, Mumbai: Reserve Bank of India.
9. NABARD (2012-2022): *Status of Microfinance in India*, Mumbai: National Bank for Agriculture and Rural Development.